

**मुख्यमंत्री ने जनपद भदोही में 'इण्डिया कार्पेट एक्सपो'  
के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारम्भ किया**

यह एक्सपो उ०प्र० की समृद्ध हस्तशिल्प परम्परा, कारीगरों की प्रतिभा और प्रदेश की बदलती औद्योगिक एवं कारोबारी क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच : मुख्यमंत्री

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के अन्तर्गत भदोही के कार्पेट को स्थान दिया गया, सरकार अब इस क्षेत्र में सिल्क क्लस्टर डेवलप करने जा रही

वाराणसी-विन्ध्य रीजनल डेवलपमेण्ट प्लान तैयार हो रहा, शीघ्र ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा

इस वर्ष इण्डिया कार्पेट एक्सपो में 227 से अधिक एग्जिबिटर्स तथा 65 देशों के 450 से अधिक फॉरेन बायर्स हिस्सा ले रहे, इनमें ब्रिक्स देशों के 106 बायर्स शामिल

उ०प्र० इण्टरनेशनल ट्रेड शो में 06 लाख से अधिक विजिटर्स आए, 650 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए, साढ़े 15 हजार करोड़ रु० से अधिक के ऑर्डर मिले

प्रदेश सरकार ने कारीगरों और हस्तशिल्पियों के हुनर को आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक बाजार से जोड़ने का कार्य किया

संत रविदास नगर और सिल्क क्लस्टर से 6,100 करोड़ रु० का निर्यात हो रहा

देश से होने वाले कुल कार्पेट निर्यात में संत रविदास नगर, मिर्जापुर और वाराणसी सिल्क क्लस्टर की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत

संत रविदास नगर में संचालित लगभग 2,500 एम०एस०एम०ई० इकाइयों का वार्षिक टर्नओवर लगभग 10 हजार करोड़ रु०, इस उद्योग से जनपद में 05 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त

उ०प्र० के पास वर्तमान में 83 जी०आई० टैग प्राप्त उत्पाद, भदोही के हैण्डमेड कार्पेट को जी०आई० टैग

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही में कार्पेट एवं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, ड्रॉइंग तथा तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध

महिलाओं की भागीदारी भदोही के कालीन उद्योग की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक प्रदेश को लगभग 50 लाख करोड़ रु० के निवेश प्रस्ताव प्राप्त, लगभग 15 लाख करोड़ रु० के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सम्पन्न, लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रु० के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग शीघ्र होने जा रही

लखनऊ : 04 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के अन्तर्गत भदोही के कार्पेट को स्थान दिया गया है। सरकार अब इस

क्षेत्र में सिल्क क्लस्टर डेवलप करने जा रही है। वाराणसी-विन्ध्य रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार हो रहा है। शीघ्र ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत जनपद संत रविदास नगर, मिर्जापुर और वाराणसी को सिल्क क्लस्टर के रूप में विकसित करते हुए यहां के उत्पादों को उनकी विशिष्ट डिजाइन, आधुनिक तकनीक और वैश्विक बाजार से जोड़ने की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी आज जनपद भदोही में अन्तरराष्ट्रीय हस्तनिर्मित कालीन व्यापार मेला 'इण्डिया कार्पेट एक्सपो' के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारम्भ करने के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 'इण्डिया कार्पेट एक्सपो' का अवलोकन किया तथा कालीन उद्योग के निर्यातकों, विक्रेताओं तथा एवं प्रमुख उद्यमियों से संवाद किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष इण्डिया कार्पेट एक्सपो में 227 से अधिक एग्जिबिटर्स तथा 65 देशों के 450 से अधिक फॉरेन बायर्स हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्रिक्स देशों से जुड़े 106 से अधिक बायर्स भी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में विदेशी खरीदारों और देशभर से आए एग्जिबिटर्स की भागीदारी यह बताती है कि भदोही के कालीन उद्योग ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाई है। यह एक्सपो केवल व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प परम्परा, कारीगरों की प्रतिभा और प्रदेश की बदलती औद्योगिक एवं कारोबारी क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच है।

संत रविदास नगर, मिर्जापुर और वाराणसी का सिल्क एवं कार्पेट क्लस्टर सदियों से अपनी विशिष्ट कला, परम्परा और हुनर के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। इण्डिया कार्पेट एक्सपो का गोल्डन जुबली संस्करण इस गौरवशाली विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रदेश सरकार ने कारीगरों और हस्तशिल्पियों के हुनर को आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक बाजार से जोड़ने का कार्य किया है। इसका परिणाम है कि भदोही सहित पूरे उत्तर प्रदेश का पारम्परिक हस्तशिल्प आज रोजगार और निर्यात का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।

उत्तर प्रदेश असीम सम्भावनाओं वाला राज्य रहा है, लेकिन बीच के कालखण्ड में बीमारू मानसिकता वाली सरकारों के कारण राज्य को बीमारू बना दिया गया। जब कोई व्यक्ति, परिवार, समाज या क्षेत्र निराशा और हताशा के साथ कार्य करता है, तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार सामने आते हैं। लम्बे समय तक प्रदेश के कारीगर को अपनी पहचान छिपाने और श्रमिक के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्नदाता किसान परेशान था, युवा पलायन के लिए मजबूर था और प्रदेश में कर्पूर, दंगा, उपद्रव तथा अराजकता का वातावरण बना रहता था। ऐसी परिस्थितियों में न तो

व्यापार आगे बढ़ सकता है, न निवेश आ सकता है और न ही देश-विदेश के खरीदार किसी क्षेत्र में आने का विश्वास कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश ने इस स्थिति को पूरी तरह बदलने का कार्य किया है। आज प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, निवेश का माहौल है, बेहतर कनेक्टिविटी है और उद्यमियों तथा कारीगरों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपीओ) योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और पारम्परिक हुनर को नई पहचान देने का अभियान शुरू किया। भदोही में कालीन उद्योग को ओडीओपीओ के रूप में आगे बढ़ाया गया।

जब वह पहली बार संत रविदास नगर आए थे, तब कालीन उद्योग से जुड़े लोगों के सामने भविष्य को लेकर अनेक आशंकाएं थीं। उन्हें बाजार, डिजाइन और हैण्डमेड कार्पेट के भविष्य को लेकर चिंता थी। सरकार ने ओडीओपीओ के माध्यम से इस उद्योग को बाजार, डिजाइन, प्रशिक्षण और विभिन्न प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराया। आज संत रविदास नगर और सिल्क क्लस्टर से 6,100 करोड़ रुपये का निर्यात हो रहा है। इससे कारीगरों, हस्तशिल्पियों और उद्यमियों की आय बढ़ी है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीन गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता मिली है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में भी तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। आज उत्तर प्रदेश देश में एमएसएमई का सबसे बड़ा आधार रखने वाले राज्यों में शामिल है। प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। इन इकाइयों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुरक्षा, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश के सवा तीन करोड़ युवा, कारीगर और हस्तशिल्पी देश में एमएसएमई एवं पारम्परिक उद्योगों से जुड़े हुए हैं।

कभी बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपनी आर्थिक मजबूती को आगे बढ़ा रहा है। सदियों से चले आ रहे हुनर को केवल विरासत के रूप में संरक्षित रखना पर्याप्त नहीं है। विकास की सोच यह होनी चाहिए कि जिस हाथ ने सदियों तक कालीन बुना है, उसी हाथ में आज नई तकनीक भी हो, नई डिजाइन भी हो और उसके पास नया बाजार भी हो। सरकार ने हुनर को इन्फ्रास्ट्रक्चर से, कारीगर को कौशल से, उद्यमी को बाजार से और स्थानीय उत्पाद को वैश्विक मांग से जोड़ने का काम किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेण्ट और अन्य व्यापारिक समझौतों का लाभ निर्यातकों को मिल रहा है। इन प्रयासों से भारतीय उत्पादों के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में नई सम्भावनाएं सृजित हो रही हैं। संत रविदास नगर के कारीगरों ने जिस हुनर और मेहनत से कालीन तैयार किए हैं, वे देश और दुनिया के

बड़े प्रतिष्ठानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। देश को नया संसद भवन मिलने के अवसर पर वहां बिछाया गया कालीन भी संत रविदास नगर के कारीगरों की कला और हुनर का उदाहरण है। यह इस बात का प्रमाण है कि भदोही का पारम्परिक हुनर आज देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं तक अपनी पहचान बना चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भदोही के हैण्डमेड कार्पेट को जी0आई0 टैग प्राप्त है। यहां इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है, जहां कार्पेट एवं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, डाइंग तथा तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (सी0ई0पी0सी0) तथा ऑल इण्डिया कार्पेट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन जैसी संस्थाएं कार्पेट इण्डस्ट्री के निर्यात, तकनीकी प्रशिक्षण और डिजाइन डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कार्पेट एक्सपोर्ट मार्ट जैसे आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भदोही को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट, इनलैण्ड वॉटर-वे और बेहतर सड़क नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों को देश-दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हुई है। गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार सहित बेहतर एक्सप्रेस-वे नेटवर्क से संत रविदास नगर और पूर्वांचल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा नोएडा क्षेत्र से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट और वाराणसी की एयर कार्गो सुविधाओं का लाभ निर्यातकों को मिलेगा। वाराणसी से इनलैण्ड वॉटर-वे के माध्यम से पूर्वी बंदरगाहों तक माल परिवहन की सुविधा भी निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कर रही है। प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेस-वे के 60 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे संचालित है।

वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में निवेश का वातावरण नहीं था। आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हो चुकी है। लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की ग्राउण्ड ब्रेकिंग शीघ्र होने जा रही है। प्रदेश में रोजगार के लाखों नये अवसर सृजित हो रहे हैं। एक्सप्रेस-वे और एयरपोर्ट नेटवर्क के साथ-साथ औद्योगिक ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रदेश में सेक्टरल पॉलिसी के माध्यम से अलग-अलग उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में कुल 14,000 कारखाने थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 35 हजार से अधिक हो गई है।

देश में मोबाइल फोन निर्माण का लगभग 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट निर्माण का लगभग 60 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के 06 नोड पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में 14 प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में न तो पहले जैसी अराजकता है, न कफर्यू और न ही दंगे का

वातावरण। अब कोई माफिया खुलेआम हथियार लहराकर धमकाने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश में बेटी, व्यापारी, उद्यमी और आम नागरिक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सुरक्षा के मजबूत वातावरण में कारीगर को काम मिलता है, व्यापारी का कारोबार बढ़ता है, निवेशक निवेश करता है और देश-विदेश के खरीदार प्रदेश में आने के लिए आकर्षित होते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में ग्रेटर नोएडा स्थित इण्डिया एक्सपो मार्ट में आयोजित उत्तर प्रदेश इण्टरनेशनल ट्रेड शो ने प्रदेश की क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया। पांच दिवसीय आयोजन में 06 लाख से अधिक विजिटर्स, डेढ़ लाख से अधिक बी2बी बैठकें, साढ़े 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर, 2,400 से अधिक प्रदर्शक तथा 650 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए। उत्तर प्रदेश इण्टरनेशनल ट्रेड शो की सफलता की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इण्डिया कार्पेट एक्सपो भी प्रदेश के उत्पादों, विशेष रूप से भदोही के कार्पेट उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में ओ0डी0ओ0पी0 व ओ0डी0ओ0सी0 नयी पहचान बना है।

देश से होने वाले कुल कार्पेट निर्यात में संत रविदास नगर, मिर्जापुर और वाराणसी के सिल्क क्लस्टर की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। अकेले संत रविदास नगर में लगभग 2,500 एम0एस0एम0ई0 इकाइयां संचालित हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये बताया गया है। इस उद्योग से जनपद में 05 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। यहां निर्मित अधिकांश कालीनों का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन सहित दुनिया के विभिन्न देशों में किया जा रहा है। भदोही के हैण्ड मेड कार्पेट को जी0आई0 टैग प्राप्त हुआ है।

भदोही के कालीन उद्योग की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यहां की महिलाओं की भागीदारी भी है। बड़ी संख्या में महिलाएं घर-गृहस्थी के संचालन के साथ-साथ कालीन उद्योग से जुड़कर परिवार की आय बढ़ाने और इस परम्परागत उद्योग को मजबूती प्रदान कर रही हैं। यह उद्योग केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि स्थानीय समाज की महिलाओं, युवाओं और कारीगरों को सम्मानजनक रोजगार एवं आत्मनिर्भरता का अवसर भी प्रदान कर रहा है। कार्पेट और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में तकनीकी शिक्षा और डिजाइनिंग एवं डाइंग में प्रशिक्षण के लिए भदोही में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी स्थापित है। कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, ऑल इण्डिया कार्पेट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन जैसी संस्थाएं कार्पेट इण्डस्ट्री, एक्सपोर्ट, टेक्निकल ट्रेनिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और हरदोई के बीच लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में पी0एम0 मित्र पार्क विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। यह इण्टीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर को नई गति देगा। कार्पेट एवं

अन्य टेक्सटाइल उत्पादों से जुड़े उद्योगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान में 83 जीआई0 टैग प्राप्त उत्पाद हैं। सरकार इन स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन के गठन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों, उद्यमियों की मेहनत और निर्यातकों की कर्मठता से प्रदेश तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

मुख्यमंत्री जी ने सीआईपीसी और कार्पेट उद्योग से जुड़ी संस्थाओं का आह्वान किया कि वे इण्डिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के साथ मिलकर इस एक्सपो को और व्यापक एवं प्रभावी बनाएं। जिस प्रकार ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इण्टरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचाने का सफल प्रयास हुआ है, उसी प्रकार भदोही के कार्पेट उद्योग को भी वैश्विक बाजार से जोड़ने के प्रयासों को और गति दी जानी चाहिए। भदोही के सिल्क एवं कार्पेट क्लस्टर में अपार सम्भावनाएं हैं। यदि सरकार, उद्योग, कारीगर, निर्यातक और संस्थाएं मिलकर काम करें, तो यह क्षेत्र न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरी दुनिया की कालीन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब प्रदेश का कारीगर रोजगार की तलाश में अपनी माटी से दूर जाने के बजाय अपने ही गांव, शहर और जनपद में अपने हुनर को आगे बढ़ाने का अवसर पा रहा है। यही बदलाव उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। जिस हाथ ने सदियों तक कालीन बुना है, उसी हाथ में आज नई तकनीक, नई डिजाइन और नया बाजार होना चाहिए। सरकार का प्रयास इसी सोच के साथ कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सशक्त बनाने का है। आज उत्तर प्रदेश अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक विकास की नई कहानी लिख रहा है। भदोही का कार्पेट उद्योग इस परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है।

सरकार का उद्देश्य केवल पारम्परिक उत्पादों को संरक्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीक और बदलती वैश्विक मांग के अनुरूप विकसित करना है। इसके लिए डिजाइन, टेक्नोलॉजी, स्कीलिंग, उत्पादन और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था को एक-दूसरे से जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा। इससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को नए बाजार उपलब्ध होंगे तथा रोजगार एवं आय के अवसरों में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा दी है। अब महिलाओं की भागीदारी केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। कार्पेट एवं सिल्क उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री जी ने सी0ई0पी0सी0 के पदाधिकारियों से कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर और स्थान सुनिश्चित किए जाएं तथा अधिक से अधिक महिला कारीगरों एवं उद्यमियों को इस उद्योग से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि उद्योग की सक्रिय भागीदार और नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे लाना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण, डिजाइन, बाजार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

कार्पेट उद्योग में लम्बे समय से कार्य कर रहे कारीगरों का अनुभव और उनकी कला अमूल्य है। एक शिक्षक और एक कारीगर वास्तव में कभी रिटायर नहीं होता। वह अपने ज्ञान, अनुभव और कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता रहता है। अनुभवी कारीगरों की विशेषज्ञता को नई पीढ़ी के प्रशिक्षण से जोड़ने की आवश्यकता है। इससे पारम्परिक हुनर का संरक्षण भी होगा और युवा कारीगर आधुनिक तकनीक एवं डिजाइन के साथ इस विरासत को आगे बढ़ा सकेंगे।

सरकार कारीगरों की भावनाओं और उनके अनुभव का सम्मान करती है। उद्योग में आवश्यक बदलाव और सुधार किए जाएंगे, ताकि पारम्परिक हुनर को आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करते हुए नई पीढ़ी के लिए रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। भदोही की पहचान केवल एक उत्पाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की कला, कौशल और कारीगरों की पीढ़ियों से चली आ रही साधना इसकी वास्तविक ताकत है। सरकार का प्रयास इस विरासत को नई तकनीक, नई डिजाइन और वैश्विक बाजार से जोड़कर इसे और अधिक सशक्त बनाने का है।

कार्यक्रम में सांसद डॉ० विनोद कुमार बिन्द, विधायक श्री दीनानाथ भास्कर, श्री विपुल दुबे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 श्री शशि भूषण लाल सुशील तथा सी0ई0पी0सी0 के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार गोम्बर व कार्पेट व्यवसायियों, उद्यमियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।